भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 965

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

खेलों के विकास और उन्नति के लिए सीएसआर से उपयोग की गई धनराशि

965. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों के विकास और उन्नति के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अंशदान से धनराशि मांगी है या उसका उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इन धनराशियों के राज्य-विशिष्ट और खेल-विशिष्ट उपयोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर के लिए व्यापक ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की अनुसूची VII के माध्यम से प्रदान की गई है। अनुसूची VII उन कार्यकलापों को इंगित करती है जो कंपनियों द्वारा पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में किए जा सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के मद संख्या (vii) का पाठ 'ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण' के रूप में है। सीएसआर एक व्यापक संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हे निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यकलापों का वार्षिक विवरण फ़ाइल करना अपेक्षित है, जो www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलापों में खर्च करने के लिए कंपनियों को कोई विशेष निर्देश जारी नहीं करती है।

(ख) से (ग): वार्षिक फाइलिंग के आधार पर वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2021-22 और 2022-23 के लिए खेल पर राज्य-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

******

दिनांक 02.12.2024 लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
अंडमान और निकोबार	1.50	-
आंध्र प्रदेश	3.09	4.75
अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.14
असम	4.02	11.31
बिहार	0.96	3.52
चंडीगढ़	0.33	0.34
छत्तीसगढ़	1.78	5.72
दादरा और नगर हवेली	0.06	0.02
दमन और दीव	-	0.05
दिल्ली	22.99	41.57
गोवा	2.82	4.62
गुजरात	8.12	7.41
हरियाणा	6.73	6.00
हिमाचल प्रदेश	2.57	10.77
जम्मू और कश्मीर	0.35	0.30
झारखंड	4.31	10.20
कर्नाटक	27.38	44.27
केरल	4.95	5.78
लेह और लद्दाख	-	0.09
मध्य प्रदेश	5.52	7.66
महाराष्ट्र	55.16	68.29
मणिपुर	0.25	1.62
मेघालय	-	1.05
मिजोरम	0.36	5.57
नागालैंड	-	0.12
ओडिशा	11.87	51.28
पुडुचेरी	0.01	0.28
पंजाब	4.13	3.85
राजस्थान	15.53	21.97
सिक्किम	0.08	2.67
तमिलनाडु	16.38	28.45
तेलंगाना	6.70	12.42
त्रिपुरा	0.10	0.31
उत्तर प्रदेश	4.23	14.72
उत्तराखंड	0.39	0.71
पश्चिम बंगाल	4.04	11.54
पैन इंडिया*	75.09	136.78
कुल	**291.85**	**526.14**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो राज्य के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****